भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3878
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

मकाचुवा में वीसैट

3878. श्री बिष्णु पद राय:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मकाचुवा, लिटिल निकोबार के फर्स्ट कैप्टन ने अंडमान और निकोबार प्रशासन को अगस्त 2023, अक्टूबर 2023 और हाल ही में 19 नवंबर 2024 को गांव में वीसैट प्रणाली लगाने के लिए बार-बार अनुरोध प्रस्तुत किए हैं;
(ख) यदि हां, तो (i) चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों (ii) बच्चों की शिक्षा, (iii) डिजिटल सेवाओं तक पंहुच (iv) व्यवसाय को आसान बनाने के लिए आवश्यक सेवाओं आदि को सुकर बनाने के लिए संपर्क की अत्यधिक आवश्यकता पर विचार करते हुए इस मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाइयों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) जनजातीय जनसंख्या की इस महत्वपूर्ण मांग की उपेक्षा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है; और
(ड.) मकाचुवा में वीसैट प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या समय-सीमा प्रस्तावित की गई है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने दिनांक 28.11.2024 को दूरसंचार विभाग से संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत मकाचुवा, लिटिल निकोबार तक वीसैट आधारित सॉल्यूशन का विस्तार करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में मकाचुवा, लिटिल निकोबार के लिए वीसैट आधारित सॉल्यूशन का विस्तार करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने 2020 में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर तथा सात अन्य द्वीपों अर्थात् स्वराज दीप (हैवलॉक), लॉन्ग आइलैंड, रंगत, लिटिल अंडमान (हटबे), कामोर्टा, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार (कैंपबेल बे) के बीच 1224 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सबमरीन ओएफसी परियोजना शुरू की है। यह इन द्वीपों को 200 जीबीपीएस तक की सबमरीन ओएफसी बैंडविड्थ प्रदान करती है।

*****